

सम्पादकीय

बुखार से मर रहे बच्चे

उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान और कर्नाटक से भी इस तरह से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों में बुखार से मरने वालों की संख्या अभी भले ही कम है, लेकिन इसका यह मतलब निकालना गलत होगा कि वहां हालात गंभीर नहीं हैं। कोरोना महामारी के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरह के बुखार का प्रकोप राज्य सरकारों का नया सिरदर्द बन गया है। सबसे गंभीर स्थिति यूपी की है। यहां फिरोजाबाद जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वायरल फीवर और डेंगू जैसे लक्षणों वाले 61 बच्चों की इस जिले में मौत हो चुकी है। आगरा जिले में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पिछले चार दिनों में वहां तेज बुखार से आठ बच्चों की जान चली गई। उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान और कर्नाटक से भी इस तरह से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों में बुखार से मरने वालों की संख्या अभी भले ही कम है, लेकिन इसका यह मतलब निकालना गलत होगा कि वहां हालात गंभीर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में अभी तक 15 बच्चों की मौत बताई जा रही है, लेकिन इस महीने तेज बुखार और फलू जैसे लक्षणों के साथ 7000 से ज्यादा बच्चे स्वास्थ्य केंद्रों पर लाए गए। साफ है कि बीमारी फैली हुई है। अगर इससे निपटने में लापरवाही हुई तो कहीं अधिक बच्चों की मौत हो सकती है। कोरोना के चलते पिछले करीब डेढ़ साल से देशवासियों की जो मनःस्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए इन बीमारियों की गंभीरता को समझना होगा।

निस्संदेह इन मौसमी बीमारियों की तूलना करोना से नहीं की जा सकती। लेकिन सर्दी-खांसी का ठोक न होना और तेज बुखार से पीड़ित बच्चों का दम तोड़ना, प्रभावित आबादी को ट्रॉमा में डालने के लिए काफी है। और करोना के खतरे से भी हम मुक्त कहां हुए हैं। आज भी रोजाना इसके लगभग 30 हजार नए मामले आ हो रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए कि पिछले डेढ़ साल में देश के स्वास्थ्य ढांचे पर असाधरण बोझ रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों ने इस दौरान अद्भुत धैर्य और क्षमता का परिचय दिया है। लेकिन और ज्यादा बोझ इस ढांचे को बैठा भी सकता है।

लहाजा, जरुरा ह कि चाह काराना हो या अन्य मासमा बीमारियां, इनके इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाए कि ये फैले ही नहीं। यहां भी सरकारी तंत्र की अहम भूमिका है, लेकिन यह भी समझना होगा कि जन-स्वास्थ्य साझा जिम्मेदारी है। चाहे साफ-सफाई रखने और पानी न इकट्ठा होने देने की बात हो या दूरी बरतने, मास्क पहनने और अन्य सावधानियां बरतने की, इन मोर्चों पर जरा सी चुस्ती चमत्कार कर सकती है, जबकि जरा सी लापरवाही किए कराए पर पानी फेर सकती है।

शाही प्रतिहार: इतिहास की किताबों में भुला दिया गया भारत का गौरवशाली अध्याय

सजाव सिह

ऐसे समय में जब सातवीं शताब्दी में मध्य एशिया और मध्य-पूर्व देशों के बीच अरब साम्राज्यवाद अपने चरम पर था तब अरब भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। इस प्रतिरोध का कारण था भारत में उत्तरी समय स्थापित शाही प्रतिहार राजवंश का शासन, जिहोंने इन लूटेरों के लिए इस्लामिक आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक अभेद्य रक्षा कवच का कानून किया और इस क्षेत्र को शान्ति और स्थिरता प्रदान की। उनके साम्राज्य ने उत्तरी भारत के सभी राजपुत वंशों को एकजुट किया। उनके सामंतों ने भी मेवाड़ के गृहिलोत (बाद का प्रसिद्ध सिसोदिया वंश), शाकंभरी के चौहान जेजाकभूत्क के चंद्रेल, गवालियर के कछवाहा, दिल्ली के तोमर और गुजरात के सोलंकी सम्भिलित थे। फिर भी यह राजवंश हमारे इतिहास की किताबों में एक सम्मानजनक उल्लेख पाने में रिफल रहा है। यह भारतीय इतिहास लेखन और पठन की सबसे बड़ी अनकही त्रासदियों में से एक है। वंशवालियों में प्रतिहारों ने स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जोड़ा है। ऐतिहासिक रूप से बात की जाए तो सबसे पहले ज्ञात प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र है। 861ई.से. के घटियां अभिलेख में उत्तरी 'विप्र' (उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति) के रूप में संबोधित किया गया है शाही प्रतिहारों की शाखा की स्थापना राजस्थान-गुजरात सीमा के पास भीनमाल (तत्कालीन का आबू क्षेत्र) के नागभट्ट प्रथम ने की थी। हमारे कुछ पाठ्यपुस्तकों में व्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिहारों को 'हुर्गुर्ज-प्रतिहार देश' के रूप में बता दिया गया है, जबकि प्रसिद्ध ऐतिहासिक रूप से सम्बोधित या संदर्भित नहीं किया है। यद्यपि इस राजवंश की स्थापना प्राचीन 'गुर्जरा' क्षेत्र (राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों) में हुई थी, परन्तु कालांतर में इस राजवंश की मध्य प्रदेश के उज्जैन और उसके बाद उत्तरप्रदेश में कन्चौज (शर्मा, शांति रानी; 'राजस्थान के शाही प्रतिहारों की उत्पत्ति और उदय' पृष्ठ 30) शासन किया। ऐतिहासिक रूप से, 'गुर्जर-प्रतिहार' वाक्यांश का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्रयोग उत्तरप्रदेश के कन्चौज संघे के लिए शासक राजा त्रिविज्या राजा द्वारा किया गया था।

सिर्फ कोरोना मोदी सरकार

रमेश सर्वाफ धमोरा

किसी भी एक देश में दिन में ढाई करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह हमारे देश के चिकित्सकर्मियों के जोश, मेहनत व जज्बे के कारण ही संभव हो पाया है। दुनिया में बहुत से देशों की तो आबादी ही ढाई करोड़ से कम है। प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन्मदिन के अवसर पर उन्हें देश-विदेश से छोटे-बड़े सभी राजनेताओं द्वारा बधाई संदेश मिल रहे थे। पार्टी कार्यकर्ता देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान प्रथानमंत्री मोदी द्वारा जन्मदिन के अवसर पर एक ऐसा कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा था जिससे दुनिया भर में भारत का सम्मान तो बढ़ा ही साथ ही देशवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर स्थापित हुआ। भारत द्वारा चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने प्रथानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में ही दो करोड़ पचास लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए देश के सभी चिकित्सकर्मी व टीकाकरण से जुड़े लोग बधाई के पात्र हैं। किसी भी एक देश में दिन में ढाई करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह हमारे देश के चिकित्सकर्मियों के जोश, मेहनत व जज्बे के कारण ही संभव हो पाया है। दुनिया में बहुत से देश

दलित सीएम से क्या कांग्रेस को फायदा होगा

अनिल सिन्हा

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की आहट से संबंधित राज्यों में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी ने उत्तराखण्ड में चार महीने में तीन मुख्यमंत्री दे दिए। कर्नाटक में (हालांकि वहां चुनाव 2023 में हैं) येदियुरपा को सीएम की कुर्सी से हटाया और गुजरात में तो मुख्यमंत्री के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला। मुख्यमंत्रियों की छुट्टी करने की इस लहर की चपेट में पंजाब भी आ गया है। वहां नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चੌहाने ने शपथ ले ली है। वह राज्य के पहले दिलत मुख्यमंत्री हैं। वहां दलितों की आबादी करीब एक तिहाई है, लेकिन उन्हें राज्य का नेतृत्व संभालने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया था। अगर सामाजिक प्रगति के लिहाज से देखें तो यह एक क्रांतिकारी घटना है। पंजाब की राजनीति में संपन्न किसानों का, बल्कि कहें जाए सम्प्रदाय का वर्चस्व रहा है। सिखों और हिंदुओं, दोनों में वे ही नेतृत्व में रहे हैं।

भारत-पाक विभाजन में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब ने ही उठाया। यह इसके बावजूद हुआ कि वहां मुस्लिम लोग की राजनीति का कोई असर नहीं था और बड़े किसानों ने एक सेकुलर गठबंधन बना रखा था। विभाजन ने राज्य की राजनीति और जीवन, दोनों को बदल दिया। बंटवारे के बाद दोनों ओर सामूहिक कल्लेआम हुए और इसका नतीजा है कि पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदुओं-सिखों की आबादी ना के बराबर रह गई। यही हाल भारत वाले हिस्से का हुआ। यहां भी डेढ़ प्रतिशत मुसलमान रह गए। पंजाब में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की आपस में गुंथी हुई जिंदगी थी। विभाजन से सब कुछ टूट गया। विभाजन के बाद वहां की राजनीति नए सिरे से शुरू हुई। इस नई राजनीति में अकाली दल और कांग्रेस के अलावा वाम दल प्रमुख भूमिका में थे।

विकास का शायद ही कोई अभिकरण हो, जो प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व से पोषित न हुआ हो। तीन दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ संस्कार और कौशल विकास से युक्त किया गया है। 17 सितंबर को हम सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वा जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर हर देशगासी ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु होने की मंगलकामनाएं की। देश और दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता आदोलन के पश्चात कई लोकप्रिय नेता हुए हैं। हर नेता की अपनी विशिष्ट कार्यशैली और क्षमता का होना स्वाभाविक है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जन्मे नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्व समुदाय पर जिस प्रकार अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी है, उसकी प्रेरक अनुगंज आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। मानवीय स्वभाव अक्सर किसी एक व्यक्तित्व में अन्य श्रेष्ठ महात्म्य जनों की तलाश करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वालों में वैशिक नेता, समाज सुधारक,

खालस्ताना आतकवाद भी बिभाजन से कम बड़ा परशाना लकड़ी नहीं आया। इसने भी वहा के जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाएं हुईं। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री बेंत सिंह की हत्या कर दी गई। राज्य के लोग इस दौर राज्य भी निकल गए। ध्यान देने लायक बात है कि इस कठिन दौर में भी खेतों और औद्योगिक उत्पादन नीचे नहीं आया। सामाजिक-आर्थिक हिसाब रहे देखें तो देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी दलित हाशिए पर ही हैं। उनकी बाजारी 32 प्रतिशत की आबादी होने के बावजूद जमीन और संपत्ति उनका न्यूनतम हिस्सा है। सिख धर्म के कारण उन्हें उस तरह के सामिजिक उपीड़न का शिकार नहीं होना पड़ता है, जो देश के बाकी हिस्सों में दिखाई देता है, लेकिन उनका आर्थिक शोषण कम नहीं है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी काफी कम है। यह भी समझना गलत नहीं होगा कि समृद्धाय के रूप में दलित आपस में एक हैं। उनका एक तिहाई हिस्सा सिख है और मजहबी सिख कहलाता है। वे खेती से जुड़े हैं और ज्यादातर भूमिहीन किसान और खेतिहर मजदूर हैं। चर्मकार और वातिकर्म समाज की तादाद भी अच्छी है। वे क्षेत्रीय आधार पर भी आपस में बंधे हुए हैं। उनकी राजनीतिक भागीदारी क्षेत्रीय आधार पर भी तय होती है।

कांशीराम ने अस्सी के दशक में दलितों को एक करने की कोशिश की थी और उनके प्रयासों का असर 1992 के चुनावों में दिखाई पड़ा। बीएसपी ने तब विधानसभा की नौ सीटें जीत ली थीं और उसे कुल 11 प्रतिशत वोट मिले। पार्टी ने 1996 का लोकसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा और तीन सीटों पर कब्जा किया। कांशीराम भी चुने गए। लेकिन कांशीराम के बाद बीएसपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर ही रहा और पंजाब में पार्टी का आधार कमजोर होता गया। 2017 देसे चुनावों में उसे सिर्फ डेढ़ प्रतिशत वोटों से संतोष करना पड़ा।

परंपरागत रूप से दलित कांग्रेस के साथ रहे हैं। उसके जनाधार र

दाशनिक और आध्यात्मिक आख्यानकर्ता तो हैं ही साथ ही मोदी जी देश के प्रशंसक अपने नेता को सर्वगुण संपन्न भी मानते हैं। विगत चार दशक राजनीतिक जीवन में होने के कारण गांव-शहर, विभिन्न जाति वर्ग, क्षेत्र और दर्हन के लोगों से संवाद करने का मुझे अवसर मिलता रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने डैसी आत्मीयता जनमानस में नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखी रह, अनिर्वचनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 वर्ष लंबी चुनावी राजनीतिक यात्रा भारतीयता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता का अद्भुत संगम है। धारा 370 व 35-ए को समाप्त करने सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद उन्मूलन, नागरिकता संशोधन कानून समेत अनेक निर्णय पीएम की वैचारिक संकल्पबद्धता को पुष्ट करते हैं।

2014 में सेंट्रल हाल में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, वंचितों और शोषितों की सरकार होगी। यह सिर्फ भाषण के शब्द नहीं थे। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व下 उनकी सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय में किसान, श्रमिक, दर्लित महिलाएं और युवा अनिवार्य घटक हैं। 12 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये समान निधि, 9 करोड़ से अधिक परिवारों में उज्ज्वला और 4 करोड़ जननथन खाते समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण

साहस और संवेदनशीलता के साथ भारत को नयी ऊँचाइयों पर पहुँचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी

धरमलाल काशक

विकास का शायद हा काइ आभकरण हा, जो प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व से पोषित न हुआ हो। तीन दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ संस्कार और कौशल विकास से युक्त किया गया है। 17 सितंबर को हम सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर हर देशवासी ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु होने की मंगलकामनाएं की। देश और दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता आदोलन के पश्चात कई लोकप्रिय नेता हुए हैं। हर नेता की अपनी विशिष्ट कार्यशैली और क्षमता का होना स्वाभाविक है। लेकिन स्वतंत्रता आदोलन के बाद जन्मे नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्व समुदाय पर जिस प्रकार अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी है, उसकी प्रेरक अनुरूप आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही। मानवीय स्वभाव अक्सर किसी एक व्यक्तित्व में अन्य श्रेष्ठ महात्म्य जनों की तलाश करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वालों में वैशिक्त नेता, समाज सुधारक,

दाशानंक जार आध्यात्मिक जागेनांकता ता हा हा साव हा मादा जा चा प्रश्नसंक अपेने नेता को सर्वगुण संपन्न भी मानते हैं। विगत चार दशक र सार्वजनिक जीवन में होने के कारण गांव-शहर, विभिन्न जाति वर्ग, क्षेत्र और वहां के लोगों से संवाद करने का मुझे अवसर मिलता रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने जैसी आत्मीयता जनमानस में नरेंद्र मोदी जी देखी प्रति देखी वह, अनिर्वचनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 वर्ष लंबी चुनावी राजनीतिक यात्रा भारतीयता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता का अनुदृत संगम है। धारा 370 व 35-ए को समाप्त करने की सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद उन्मूलन, नागरिकता संशोधन कानून समेत अनेक निर्णय पीएम की वैचारिक संकल्पबद्धता को पुष्ट करते हैं।

2014 में सेंट्रल हॉल में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, वीर्यों और शोषितों की सरकार होगी। यह सिर्फ भाषण के शब्द नहीं थे। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व下 12 उनकी सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय में किसान, श्रमिक, दलिलत महिलाएं और युवा अनिवार्य घटक हैं। 12 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये समान निधि, 9 करोड़ से अधिक परिवारों में उज्ज्वला और 4 करोड़ जननथन खाते समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण

बीएसपी को आर से सध लगा था, लेकिन अब दालित वापस इस आर आ गए हैं। कांग्रेस ने 2017 के चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 34 में से 22 सीटें जीती थीं। इसे ध्यान में रख कर ही अकाली दल ने आने वाले चुनावों के लिए मायावती से गठबंधन किया है। उसने बीएसपी को बीस सीटें दी हैं। अकाली दल ने यह बाद भी किया है कि उसकी सरकार आई तो वह दलित को उपमुख्यमंत्री पद देगा। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि दलित समुदाय को वह किस तरह संतुष्ट करे। सत्ता-विरोधी भावना से डरी हुई कांग्रेस के लिए दलित समुदाय का वोट काफी मायने रखता है। कांग्रेस के इस दांव ने अकाली दल के उपमुख्यमंत्री पद के बाद को तो निरर्थक बना ही दिया है, लेकिन क्या दलित समुदाय का दिल जीतने के लिए यह काफी होगा

निश्चित रूप से विपक्षी दल इस कदम के पीछे छपी कांग्रेस की मजबूरियां गिनाएंगे। सच भी है, पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कुछ तात्कालिक कारण भी काम कर रहे थे। एक बड़ा कारण तो यह था कि लंबे समय से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे कैफ्टन अमरिंदर की जगह भरने के लिए ऐसे नेता की जरूरत थी, जो पार्टी के भीतर का शक्ति-संतुलन स्थिर रखे। नवजोत सिंह सिद्धू से खाए खाए कैफ्टन ने उनके खिलाफ ऐसा बयान दे दिया, जिससे विपक्ष को तिल मिल गया है। वह जब चाहे इसका ताड़ बना सकता है। जाटों के दो बड़े नेता सुखिंदर सिंह रंथांग और सुनील जाखड़ के नाम पर सहमति न हो पाना भी एक कारण रहा, जिसकी वजह से अंत में चची का नाम तय करना पड़ा। इन सबके बावजूद कांग्रेस का यह फैसला दूरगमी परिणाम ला सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती कांग्रेस पर निशाना साधती रही हैं। प्रतीकों की राजनीति के दौर में यह कदम अनन्देखा नहीं रह सकता। यह भी ध्यान रखना होगा कि तमाम किंतु-परंतु के बावजूद यह सामाजिक प्रगति की ओर एक कदम है।

पर पहुँचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के यज्ञ से निकले आंकड़े हैं। विकास का शायद ही कोई अभिकरण हो, जो प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व से पोषित न हुआ हो। तीन दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ संस्कार और कौशल विकास से युक्त किया गया है। स्वभाषा के आधार पर राष्ट्र के विकास को नई दिशा दी जा रही है। आर्थिक सुधारों के इस क्रम में श्रम सुधारों के जरिए श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त हों, यह व्यवस्था कारगर रूप से संचालित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हर भारतीय के जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का दो दशक का कार्यकाल जनकल्याण व सुराज की दृष्टि से मील का पथर साबित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालते ही सुशासन का सर्वस्पर्शी मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे देशभर की राज्य सरकारों ने अलग-अलग रूपों में अपनाया है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अब वह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दर्शन से सुशासन को नया सोपान दे रहे हैं। देश के 130 करोड़ नागरिकों के प्रति उनकी सेवा भारत को इस बात से ही समझा जा सकता है कि वह स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रति पीएम मोदी का विशेष लगाव रहा है। नवंबर 2018 में बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को सबोधित करते हुए पीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी के विकास प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। इस अवसर पर राज्य के प्रति अपने भावनात्मक लगाव को दोहराते हुए उन्होंने कहा था कि जिस राज्य को हमने जन्म दिया, पाला-पोसा उसके विकास की जिमेदारी भी हमारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीस दिन सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाने का मिर्जिय लिया है। आज देश विश्व की महाशक्ति बनने की राह पर है।

साहस और संवेदनशीलता के साथ भारत को नयी ऊँचाइयों पर पहुँचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी

धरमलाल कौशिक

विकास का शायद ही कोई अभिकरण हो, जो प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व से पोषित न हुआ हो। तीन दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ संस्कार और कौशल विकास से युक्त किया गया है। 17 सितंबर को हम सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर हर देशवासी ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु होने की मंगलकामनाएं की। देश और दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात कई लोकप्रिय नेता हुए हैं। हर नेता की अपनी विशिष्ट कार्यशैली और क्षमता का होना स्वाभाविक है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जन्मे नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्व समुदाय पर जिस प्रकार अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी है, उसकी प्रेरक अनुरूप आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। मानवीय स्वभाव अक्सर किसी एक व्यक्तित्व में अन्य श्रेष्ठ महात्म्य जनों की तलाश करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वालों में वैशिक नेता, समाज सुधारक, दर्शनिक और आध्यात्मिक आख्यानकर्ता तो ही ही साथ ही मोदी जी के प्रशसंक अपने नेता को सर्वगुण संपन्न भी मानते हैं। विगत चार दशक से सार्वजनिक जीवन में होने के कारण गांव-शहर, विभिन्न जाति वर्ग, क्षेत्र और गहां के लोगों से संवाद करने का मुझे अवसर मिलता रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने जैसी आत्मीयता जनमानस में नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखी वह, अनिरचनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 वर्ष लंबी चुनावी राजनीतिक यात्रा भारतीयता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता का अद्दुत संगम है। धारा 370 व 35-ए को समाप्त करने, सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद उन्मूलन, नागरिकता संशोधन कानून समेत अनेक निर्णय पीएम की वैचारिक ग्रंथावली को पास करते हैं।

संकल्पबद्धता का पृष्ठ करत है। 2014 में स्टॉल हॉल में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, वंचितों और शोषितों की सरकार होगी। यह सिर्फ भाषण के शब्द नहीं थे। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय में किसान, श्रमिक, दलित, महिलाएं और युवा अनिवार्य घटक हैं। 12 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये समान निधि, 9 करोड़ से अधिक परिवारों में उज्ज्वला और 42 करोड़ जननथन खाते समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के यज्ञ से निकले आंकड़े हैं। विकास का शायद ही कोई अभिकरण हो, जो प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व से पोषित न हुआ हो। तीन दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ संस्कार और कौशल विकास से युक्त किया गया है। स्वभाषा के आधार पर राष्ट्र के विकास को नई दिशा दी जा रही है। आर्थिक सुधारों के इस क्रम में श्रम सुधारों के जरिए श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त हों, यह व्यवस्था कारगर रूप से संचालित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हर भारतीय के जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का दो दशक का कार्यकाल जनकल्पना व सुराज की दृष्टि से मील का पथर साबित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालते ही सुशासन का सर्वस्तरी मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे देशभर की राज्य सरकारों ने अलग-अलग रूपों में अपनाया है।

